



स्वच्छ भारत मशिन-शहरी

प्रलमिस के लयि:

स्वच्छ भारत मशिन-शहरी, खुले में शौच, कचरा मुक्त स्टार रेटगि

मेन्स के लयि:

स्वच्छ भारत मशिन, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) ने देश भर में [स्वच्छ भारत मशिन-शहरी](#) (SBM-U 2.0) के दूसरे चरण के योजना निर्माण और कार्यान्वयन के मूल्यांकन तथा इसमें तेज़ी लाने के लिये एक समीक्षा-सह-कार्यशाला का आयोजन किया।

- वर्ष 2022 के लिये [वशिव स्वास्थय संगठन](#) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) द्वारा जल, साफ-सफाई और स्वच्छता पर [संयुक्त नगिरानी कार्यक्रम](#) (JMP) द्वारा जारी की गई हालिया रपिर्ट के बाद [खुले में शौच](#) का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। रपिर्ट में बताया गया है कि भारत में कुल आबादी के लगभग 17% लोग खुले में शौच करते हैं।

स्वच्छ भारत मशिन-शहरी:

- परचिय:**
 - शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, स्वच्छता और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में [आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय](#) द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को [स्वच्छ भारत मशिन-शहरी](#) (SBM-U) शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य पूरे भारत के शहरों और कस्बों को स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाना है।
- स्वच्छ भारत मशिन-शहरी 1.0:**
 - SBM-U का पहला चरण शौचालयों तक पहुँच प्रदान करके और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देकर शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित था।
 - SBM-U 1.0 अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा और 100% शहरी भारत को ODF घोषित किया गया।
- स्वच्छ भारत मशिन-शहरी 2.0 (2021-2026):**
 - वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित SBM-U 2.0, इसी योजना के पहले चरण की नरितरता है।
 - इसके दूसरे चरण का लक्ष्य ODF के लक्ष्यों के साथ ही ODF+ और ODF++ के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तथा शहरी भारत को कचरा-मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।
 - इसमें स्थायी स्वच्छता प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- उपलब्धियाँ:**
 - खुले में शौच से मुक्त (ODF):**
 - शहरी भारत खुले में [शौच से मुक्त](#) हो गया है, सभी 4,715 शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies- ULB) पूरी तरह से ODF हो गए हैं।
 - 3,547 शहरी स्थानीय निकाय कार्यात्मक और स्वच्छ सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा के साथ ODF+ की श्रेणी में हैं तथा 1,191 ULB मल कीचड़ के संपूर्ण प्रबंधन के साथ अब ODF++ की श्रेणी में आ गए हैं।
- 14 शहर **WATER+** प्रमाणित हैं, जिसका अर्थ है कि यहाँ अपशिष्ट जल का उपचार और इसका इष्टतम पुनः उपयोग किया जाता है।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण:**
 - 97% वार्डों में 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण और देश के सभी ULB में 90% से अधिक वार्डों में नागरिकों द्वारा उत्पन्न किये जा रहे कचरे का स्रोत पर पृथक्करण से सहायता मिली है, इस कारण [भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण](#) वर्ष 2014 के 17% से 4 गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 75% हो गया है।
- अपशिष्ट मुक्त शहर:**

- जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया अपशष्टि मुक्त शहर (GFC)-स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल पहले वर्ष में केवल 56 शहरों से बढ़कर अब तक 445 शहरों तक पहुँच गया है, अक्टूबर 2024 तक कम-से-कम 1,000 3-स्टार GFC बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2023-24 के बजट में सूखे और गीले अपशष्टि के वैज्ञानिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान देकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण की भारत की प्रतिबद्धता को और मज़बूत किया गया है।

खुले में शौच से मुक्त भारत की स्थिति:

- **ODF:** किसी क्षेत्र को ODF के रूप में अधिसूचित अथवा घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है।
- **ODF+:** यह दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है तथा सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय अच्छी तरह से बनाए गए हों, उनका अच्छा रखरखाव किया जा रहा हो और वे अच्छे से कार्य कर रहे हों।
- **ODF++:** यह दर्जा तब दिया जाता है जब कोई क्षेत्र पहले से ही ओडीएफ+ की श्रेणी में आता हो और मल कीचड़/सेप्टेज तथा सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित एवं उपचारित किया जाता है, जिसमें अनुपचारित मल कीचड़ और सीवेज को खुली नालियों, जल नकियों अथवा क्षेत्रों में छोड़ा या डंप नहीं किया जाता हो।

JMP रपिर्त की मुख्य विशेषताएँ:

- **खुले में शौच के आँकड़े:**
 - रपिर्त से पता चलता है कि भारत में 17% ग्रामीण आबादी अभी भी खुले में शौच करती है।
- **बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच:**
 - भारत में एक-चौथाई ग्रामीण आबादी की "न्यूनतम बुनियादी" स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।
 - बुनियादी सेवाओं को बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें एक परिवार दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं।
- **वर्ष 2015 के बाद हुई प्रगति:**
 - यह रपिर्त वर्ष 2015 के बाद से प्रगति पर नज़र रखती है जब स्वच्छता के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
 - वर्ष 2015 में लगभग 41% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती थी, जो वर्ष 2022 में घटकर 17% रह गई।
 - स्वच्छता सुविधाओं के संदर्भ में वर्ष 2015 में 51% घरों में न्यूनतम बुनियादी स्वच्छता थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 75% हो गई।
- **खुले में शौच के आँकड़ों में गिरावट की दर:**
 - भारत में खुले में शौच के आँकड़ों में 3.39% की वार्षिक औसत गिरावट दर की गई है।
 - यदि यह गिरावट दर जारी रही, तो खुले में शौच-मुक्त स्थिति हासिल करने में लगभग चार से पाँच वर्ष लगेंगे।
- **सफ़ाई:**
 - खुले में शौच के स्थान पर शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये व्यवहार परिवर्तन के महत्त्व पर बल देना।
 - ODF स्थिति का सटीक पता लगाने के लिये शौचालयों के उपयोग के प्रत्येक व्यावहारिक परिवर्तन की दर निर्धारित करना और उसे मापना।
 - इसके अनुमूलन की दृष्टि में कार्य कर खुले में शौच के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करना।
 - सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिये स्वच्छता प्रथाओं की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना।
 - JMP रपिर्त के नक्शों के आधार पर मील के पत्थर के रूप में भारत में ODF का पुनर्मूल्यांकन करना और खुले में शौच को संबोधित करना तथा स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिये व्यापक उपाय करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. "जल, स्वच्छता और स्वच्छता आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशति परिणामों के साथ समन्वित किया जाना है।" WASH योजना के संदर्भ में कथन का परीक्षण कीजिये। (2017)

प्रश्न. सामाजिक प्रभाव, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में कैसे योगदान दे सकता है? (2016)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

